जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 163 दिनांक:27-05-2022 शुक्रवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

नई दिल्ली में गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई।

मोदी सरकार ने घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक कूटनीति में खींची है बड़ी लकीर, अब 'विकास' बनने लगा है चुनाव को जिताने वाला मुद्दा

गुजरात से फिर पकड़ाई करोड़ों की ड्रग्स

नई दिल्ली (ईएमएस)गुजरात से ड्रग्स का मिलना बदस्तूर जारी है। राजस्व खुफिया निदेशालय - डीआरआई ने गुजरात के बंदरगाह से 52 किलोग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में 500 करोड़ रुपये से अधिक है। ये खेप ईरान के मुंद्रा बंदरगाह से नमक बताकर लाई गयी थी। डीआरआई के अधिकारियों को ईरान से आयात की जा रही कुछ खेपों में नशीली दवाओं के होने की आशंका थी। ऐसे नशीली दवाओं पर रोक के लिए, डीआरआई द्वारा ठऑपेरशन नमकीनठ शुरू किया गया था। ईरान के मुंद्रा बंदरगाह से आई खेप में 25 मीट्रिक टन के वजन वाले सामान्य नमक के 1000 बैग होने की घोषणा की गई थी। इस खेप की जांच 24 से 26 मई तक की गई।

जांच के दौरान कुछ बैग संदिग्ध पाए गए। इन बैगों में पाउडर के रूप में एक खास गंध वाला पदार्थ पाया गया। उन संदिग्ध बैगों से नमूने लिए गए और गुजरात सरकार के फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया, जिन्होंने इन नमूनों में कोकीन की मौजूदगी की सूचना दी। डीआरआई ने अब तक 52 किलो कोकीन बरामद किया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जांच और जब्ती की कार्यवाही जारी है। उक्त आयात खेप में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका की भी डीआरआई द्वारा जांच की जा रही है।

साल 2021-22 में डीआरआई ने देश भर से 321 किलोग्राम कोकीन जब्त की थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत 3200 करोड़ रु. है। पिछले एक महीने में, डीआरआई ने कुछ महत्वपूर्ण मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कांडला बंदरगाह पर जिप्सम पाउडर की आयात हुई खेप से 205 किलोग्राम हेरोइन, पिपावाव बंदरगाह पर 395 किलोग्राम हेरोइन, दिल्ली एयरपोर्ट के एयर कार्गो काम्प्लेक्स 62 किलोग्राम हेरोइन,लक्षदीप द्वीप समूह के तट पर (भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक संयुक्त अभियान में) 218 किलो हेरोइन बरामद हुई है।

अजमेर शरीफ में शिवालय होने का दावा, दरगाह में स्वास्तिक क्यों?

अजमेर (ईएमएस)। राजस्थान के अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब दरगाह को महाराणा प्रताप सेना ने मंदिर होने का दावा किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर इसकी जांच कराने के लिए कहा है। महराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने तस्वीर भेजी है, जिसमें अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर स्वस्तिक के निशान बने हुए हैं। सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार दावा कर रहे हैं, कि अजमेर की हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था जिसे दरगाह बना दिया गया।

परमार का दावा है कि दरगाह में स्वस्तिक का क्या काम? ये जांच का विषय है। हमने मुद्दा उठाया है, सरकार को जांच करनी चाहिए। महराणा प्रताप सेना ने राजस्थान सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। सेना के प्रमुख परमार ने कहा, एक हफ्ते में जांच नहीं हुई, तब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। फिर भी कोई समाधान नहीं निकला, तब एक बड़ा आंदोलन होगा। महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता 2000 की संख्या में अजमेर जाकर आंदोलन करेंगे। साथ ही कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है।

अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतरी, मोदी सरकार ने जनता को छला: कांग्रेस

नई दिल्ली(ईएमएस)। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि अब अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतर चुकी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने के मौके पर आठ साल, आठ छल, भाजपा सरकार विफल शीर्षक वाली एक पुस्तिका भी जारी की।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी आये तो महंगे दिन लाये। किसानों की आमदनी भी नहीं हुई दोगुना, बल्कि उन्हें दर्द मिला सौ गुना। उन्होंने दावा किया, मोदी आये तो मंदी लेकर आए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं पर से ध्यान भटकाने के लिए अब छल, कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रही है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने महंगाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये से अधिक और सरसों का तेल 200 रुपये से अधिक कीमत पर मिल रहा है।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून छह दिन रुकने के बाद श्रीलंका पहुंचा

ई दिल्ली (ईएमएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्से में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगले 48 घंटे में मॉलदीव, लक्षद्वीप के आसपास के हिस्सों में इसके पहुंचने के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून छह दिन रुकने के बाद श्रीलंका पहुंच चुका है।

आईएमडी ने कहा कि मॉनसून के केरल की ओर बढ़ने पर पूरी नजर रखी जा रही है। सामान्ये तौर पर मॉनसून केरल में एक जून को पहुंचता है अब इसके चार दिन पहले पहुंचने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून ने इस माह बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी के कारण तेजी पकड़ ली है। मॉनसून वक्त से काफी पहले 16 मई को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पहुंच गया था और चक्रवात के शेष प्रभाव के चलते इसके आगे बढ़ने के आसार थे।

आज भारत जी20 देशों के समूह में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था : पीएम मोदी

हैदराबाद (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 20 वर्ष पूरे होने पर अपना संबोधन कर कहा कि हम सभी आईएसबी की स्थापना के 20 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज अनेक साथियों को डिग्री और गोल्ड मेडल मिलें हैं। आईएसबी को सफलता के पड़ाव पर पहुंचाने में अनेकों लोगों की तपस्या रही है। मैं आज उन सभी को याद करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साल 2001 में पूर्व पीएम अटल जी ने इस देश को समर्पित किया था। तब से लेकर आज तक लगभग 50 हजार एक्ज़ीक्यूटिव यहां से ट्रेंड होकर निकले हैं। आज आईएसबी एशिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत जी20 देशों के समूह में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। स्मार्टफोन डाटा कन्ज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा, रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मिन्स बिजनेस। आज हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वहां दुनिया को लीड कर सकते हैं। इसकारण आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के उत्पाद को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि हम अक्सर इंडियन सल्यूशन को विश्व स्तर पर लागू होते हुए देखते हैं। इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को, देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। हमारे देश में रिफॉर्म की जरूरत हमेशा महसूस की जाती थी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी देखी। 2014 के बाद से देश राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में भी हमने कई रिफॉर्म किए हैं। इसी का परिणाम है कि बीते 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 से बढ़कर 600 से भी अधिक हो गई है। देश में मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 90 हजार से बढ़कर 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुनवाई योग्य है या नहीं? इस पर सुनवाई अब 30 मई को

वाराणसी (ईएमएस)। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत सुनवाई कर सकती है या नहीं इस मामले में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जिला जज की अदालत में प्रकरण की पोषणीयता को लेकर अदालत पर सुनवाई होनी है। संभव है इस मामले को लेकर अदालत किसी निर्णय पर भी पहुंच जाए। इस लिहाज से वाराणसी ही नहीं बल्कि देश के इस चर्चित मामले में केस को लेकर लोगों की निगाह जिला जज की अदालत पर लगी हुई है। वहीं डेढ़ घंटे तक सुनवाई के बाद ज्ञानवापी केस में गुरुवार की सुनवाई चार बजे खत्म हो गई। वहीं जिला जज की अदालत ने अब इस मामले में 30 मई को अगली सुनवाई की तिथि दी है।

गुरुवार को दोपहर ढाई बजे के बाद जिरह शुरु हुई तो दोनों पक्षों ने तर्क और दस्तावेजों को सामने रखा। इस दौरान आधे घंटे तक मुस्लिम पक्ष की ओर से जिरह की गई। पूरे समय मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने वर्शिप एक्ट के हवाले से तमाम तरह ही दलीलें पेश की हैं। इस दौरान अदालत के भीतर शोर शराबा होने पर कोर्ट में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही दलीलों को सुनकर अपनी बातें अदालत के समक्ष रखेगा। वहीं गुरुवार को हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने प्राप्त शिवलिंग और उसकी सुरक्षा को लेकर शिवलिंग से छेड़छाड़ किए जाने का भी आरोप लगाया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में 1991 के पूर्व भी शृंगार गौरी के पूजन की जानकारी देते हुए वर्शिप एक्ट से अलग मामला बताया। इसके बाद शाम चार बजे डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद अदालत की कार्यवाही खत्म हो गई।

ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई 26 मई से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हो रही है। वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से इसकी तैयारी एक दिन पूर्व से चल रही थी। दोनों ओर से दिए जाने वाले साक्ष्य और दलीलों से मुकदमे का अस्तित्व तय हो पाएगा। प्रतिवादी पक्ष यह साबित करने सफल रहा कि मुकदमा पोषणीय नहीं है तो अभी तक हुई सारी कार्यवाही यहीं रुक जाएगी। वहीं वादी पक्ष अदालत को यह बताने में सफल रहा कि मुकदमा सुनने योग्य है तो सुनवाई आगे बढ़ेगी। मुकदमे की सुनवाई के बाद निचली अदालत का जो फैसला होगा उस पर दोनों पक्षों के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है।

जिला जज की अदालत में मुकदमे की पोषणीयता पर होने वाली सुनवाई में अपनी बात रखने का मौका सबसे पहले प्रतिवादी पक्ष को मिला है। इनकी ही मांग थी कि सबसे पहले अदालत यह तय करें कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था। प्रतिवादी पक्ष जब अपनी दलील पूरी कर लेगा तो वादी पक्ष को मौका मिलेगा। इसे लेकर दोनों पक्षों ने जोरदार तैयारी की है।

प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का कहना है कि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। कहा कि हमारे पास अदालत के सामने रखने के तमाम साक्ष्य व नजीर हैं। इससे मैं साबित कर दूंगा मुकदमा पोषणीय नहीं है। इस पर तो पहले ही सुनवाई होनी चाहिए थी।

अखिलेश यादव की टिप्पणी से आहत केशव प्रसाद मौर्य

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूपी विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन यानी सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच तू-तड़ाक की भाषा में तीखी बहस हो गई थी। गुरुवार को इस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भावुक होकर कहा कि मेरे पिता नहीं हैं। अखिलेश यादव के इस बयान से मैं काफी आहत हूं। उन्होंने मेरे दिवंगत पिता पर टिप्पणी कर पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सदन में इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ उपनेता होने के नाते सदन में अपनी बात रखी थी लेकिन नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कहीं से भी संसदीय और शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम से पूछा था कि आपके जिले के मुख्यालय की सड़क किसने बनवाई? इस पर डिप्टी सीएम ने पिछली सपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग सड़क, एक्सप्रेस-वे जैसी बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सैफई बेचकर ये सब करवाया हो। डिप्टी सीएम के इस बयान पर भड़के अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि 'तुम अपने पिजा जी से लाते हो ये सब बनवाने के लिए...' इस पर सदन में माहौल काफी गर्म हो गया। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच हुई इस तीखी बहस के बाद सीएम योगी को मोर्चा सम्भालना पड़ा। सीएम ने कहा कि सदन में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आप भाषा को लेकर असहमति जता सकते हैं लेकिन सदन में तू-तू, मैं-मैं नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

बंगाल में विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को बनाया जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के लिए जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा।उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बसु ने कहा, ''राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को आज अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।''बंगाल राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कानून के अनुसार, राज्यपाल राज्य के 17 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। उनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, विद्यासागर विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय शामिल हैं।

शांतिनिकेतन में विश्वभारती के लिए, राज्यपाल प्रधान या रेक्टर हैं, जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चांसलर हैं। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, धनखड़ ने आरोप लगाया था कि बंगाल में 25 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उनकी सहमति के बिना नियुक्त किया गया था।

हालांकि, ममता बनर्जी सरकार ने दावा किया था कि राज्यपाल को सर्च कमेटी द्वारा चुने गए कुलपतियों के नामों को मंजूरी देनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया, तो शिक्षा विभाग के पास अपने फैसले पर आगे बढ़ने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को वैधानिक करार दिया, कहा- सेक्स वर्कर्स के काम में पुलिस हस्तक्षेप न करे

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश की सर्वोच्च अदालत ने वेश्यावृत्ति को वैधानिक करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति से सेक्स वर्क करने वाले महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में 6 निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं।

कोर्ट ने कहा, जब यह साफ हो जाता है कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करे, क्योंकि इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना अवैध नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है।

कोर्ट ने कहा, एक महिला सेक्स वर्कर है, सिर्फ इसलिए उसके बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी है। अगर नाबालिग को वेश्यालय में रहते हुए पाया जाता है, या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है। कोर्ट ने कहा, सेक्स वर्कर्स को भी नागरिकों के लिए संविधान में तय सभी बुनियादी मानवाधिकारों और अन्य अधिकारों का हक है। बेंच ने कहा, पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। न ही उन्हें किसी भी यौन गतिविधि के लिए मजबूर करना चाहिए।

सिब्बल के बाद सपा ने जयंत चौधरी को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी

लखनऊ(ईएमएस)। राज्यसभा में तीन सदस्य भेजने की तैयारी में लगी समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को अपना संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल के बाद जयंत चौधरी को उच्च सदन भेजने का समाजवादी पार्टी का निर्णय 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को उच्च सदन में भेजकर समाजवादी पार्टी सहयोगियों को बड़ा संदेश देने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्दी ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

सरकार ने फिलहाल जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव करने का फैसला टाला

- जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की हो सकती है बैठक

नई दिल्ली (ईएमएस)। ऐसे समय में जब चीजों की कीमतें पहले से ही आसमान पर हैं, केंद्र व राज्य सरकारें टैक्स की दरों में कोई बदलाव कर नया रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। दरअसल पहले तो कोरोना महामारी ने दुनिया भर को प्रभावित किया। उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई ने हालात बदतर बना दिया। इसके चलते अनाजों की कमी हो रही है और इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये बाहरी फैक्टर चीजों की कमी और महंगाई को प्रभावित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव को फिलहाल के लिए टालने का फैसला लिया है। जीएसटी के बारे में अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है। हालांकि लंबे अंतराल से काउंसिल की बैठक नहीं हुई है। जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक पिछले साल सितंबर में लखनऊ में हुई थी। उन्होंने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और बैठक को इसके बाद के लिए टाला नहीं जा सकता है। जानकारी के मुता?बिक जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की बैठक की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि संसद सत्र से पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है। हालांकि इस बात की संभावना काफी कम हैं कि बड़ी संख्या में चीजों के ऊपर लेवी लगाई जाए, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल भारत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची महंगाई की मार से सिर्फ आम लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं. अब महंगाई सरकार के फैसलों पर असर डालने लगी है और इसके कारण जीएसटी के स्लैब व दरों में बदलाव की योजना को बाद के लिए टाल दिया गया है।

सितंबर में हुई पिछली बैठक में काउंसिल ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह को जीएसटी दरें तार्किक बनाने की संभावनाओं पर गौर करने का काम दिया था। समूह को काम यह दिया गया था कि वे गुवाहाटी में नवंबर 2017 में हुई बैठक में कई कमॉडिटीज और सर्विसेज पर जीएसटी दरों में की गई कटौती की समीक्षा करें। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई उस बैठक में 28 फीसदी के सबसे ऊंचे स्लैब में महज 50 सामान रखे गए थे। उस बैठक में काउंसिल ने 178 सामानों पर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी थी। इनके अलावा कई सामानों पर टैक्स की दर 5 फीसदी से घटाकर शून्य करने का भी फैसला लिया गया था।

गौरतलब है ?कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के समय जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई थी, लेकिन अब यह सुधर चुका है। अप्रैल 2022 में टोटल जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए रहा था। अप्रैल 2022 में सरकार को सेंट्रल जीएसटी से 33,159 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा सरकार को स्टेट जीएसटी से 41,973 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी से 81,939 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सामानों के आयात से प्राप्त 36,705 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी शामिल है। सरकार को सेस से 10,649 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें सामानों के आयात से मिले 857 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इस तरह अप्रैल 2022 में करीब 1.68 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बना।

कार्टून कोना

तीन संसदीय क्षेत्रों और सात विधानसभा सीटों पर 23 जून को चुनाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। चुनाव आयोग 23 जून को पांच राज्यों और दिल्ली में तीन संसदीय क्षेत्रों और सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराएगा और वोटों की गिनती 26 जून को होगी। ये उपचुनाव पंजाब में संगरूर संसदीय क्षेत्र और उत्तरप्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में, जबकि विधानसभा क्षेत्र अगरतला, टाउन, बोरदीवाला, सूरमा (एससी) और त्रिपुरा के जुबराजनगर, आंध्र के आत्मकुर, दिल्ली के राजिंदर नगर और झारखंड के मदार में होने वाले हैं। आयोग के आदेश के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना की तिथि 30 मई होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून होगी और अगले दिन पर्चो की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून है।

ठआदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव वाले संसदीय/विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है।ठ चुनाव आयोग ने कहा कि इन चुनावों के लिए 1 जनवरी, 2022 के संदर्भ में उपरोक्त विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो।

मतदाता फोटो पहचानपत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा, हालांकि, आधार या मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र को भी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

तेल आयात के लिए भुगतान प्रणाली तलाश रही केंद्र सरकार!

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए केंद्र सरकार मास्को से तेल आयात के लिए एक भुगतान प्रणाली की तलाश कर रही है। रूस पर लागू प्रतिबंधों के साथ ही स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की गुंजाइश व्यापार को जारी रखने के एक माध्यम से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार देने तक पहुंच गया है। आ?धिका?रिक सूत्रों ने कहा ?कि हमने यूरोप द्वारा रूबल में भुगतान के बारे में सुना है। अतीत में भारत के पास रुपया-रूबल भुगतान प्रणाली थी। मुझे नहीं लगता कि हम अब तक किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। कुछ चर्चाएं चल रही हैं।

दिल्ली में स्टेडियम में कुत्ता घुमाने की मांग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी का तबादर्ली

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में स्टेडियम में कुत्ता घुमाने की मांग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया है। संजीव खिरवार की आईएएस पत्नी रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। बताते चलें कि त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर आईएएस अधिकारी द्वारा कुत्ते टहलाने के कारण खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया था। खिलाड़ियों के मुताबिक पहले वे आठ बजे तक प्रैक्टिस करते थे लेकिन बाद में गार्ड 7 बजे ही खिलाड़ियों को ट्रैक से हटाने लगे थे।

इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में सभी सरकारी खेल केंद्रों को रात 10 बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।यह निर्देश मीडिया में आईएएस अधिकारी वाली खबर आने के बाद दिया गया है।

चुनाव आयोग हुआ सख्त, 2 हजार से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली (ईएमएस)। चुनाव व्यवस्था के हिमायती चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए देश में 2,100 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपीएस) की सूची में डाला गया है। अब इन दलों पर कड़ी कर्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इनमें से तीन चौथाई से ज्यादा दलों ने योगदान रिपोर्ट, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनाव में हुए खर्च से जुड़ी रिपोर्ट, पता बदलने की जानकारी संबंधी संवैधानिक जरूरतों का पालन नहीं किया है। एक तरह से इन दलों ने किसी भी तरह की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी गैरमान्यता प्राप्त पार्टियों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 के तहत ग्रेडिंग की कार्रवाई शुरू की गई है।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2001 में इन पार्टियों की संख्या 694 थी, जो 2021 में बढ़कर 2100 तक पहुंच गई। हालांकि 2019 के चुनाव में महज 623 पार्टियों ने ही हिस्सा लिया था। अब इन पार्टियों को अपंजीकृत करने के लिए सरकार के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग ने जारी किए गए अपने निर्देशों में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों के अंदर ही ऐसी 87 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद जांच में नाम और पता सत्यापित नहीं किया जा सका। अब उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ऐसे दल जिनके नाम सूची में हैं, वे 30 दिनों के अंदर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास मौजूदा और वर्षवार योगदान की रिपोर्ट, ऑडिट अकाउंट के साथ बैंक लेनदेन की अधिकृत हस्ताक्षर की कॉपी के साक्ष्य जमा कर सकते हैं।

ऐसी पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की अलग-अलग सूची सीई

जन हितैषी

अमेरिका की मजबूरी

जापान में क्वाड समिट में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम और वैक्सीन को सराहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पीएम मोदी के काम की तारीफ की। बाइडेन ने महामारी से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है। इसके अलावा बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में भी बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी है। हमारे साझा हितों और मूल्यों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के बंधन को मजबूत किया है। बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भारत के साथ धरती की अब तक की सबसे अच्छी दोस्ती करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोरोना से लेकर यूक्रेन मसले तक बाइडेन की मोदी की तारीफ के मायने देखें तो पता चलेगा कि ना चाहते हुए भी अमेरिका आज भारत से बैर ले पाने की स्थिति में नहीं है। रूस-यूक्रेन जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। हालांकि, इस जंग के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। एक पखवाड़े में दस से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री या बड़े अधिकारियों ने भारत का दौरा किया है। इन देशों में प्रमुख रूप से रूस, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, ग्रीस, ओमान, श्रीलंका, मैक्सिको और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री, जापानी प्रधानमंत्री और अमेरिका के डिप्टी एनएसए शामिल रहे हैं। दुनियाभर के प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों के लगातार भारत दौरे ने यह साबित किया है कि रूस-यूक्रेन जंग से उपजे हालात में भी दुनिया के प्रमुख देशों को भारत की अहमियत पता है। यह दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव की निशानी है। रूस यूक्रेन जंग में भारत की तटस्थता नीति की निंदा करने के बावजूद इसका असर भारत अमेरिका के संबंधों पर नहीं पड़ा। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच कई स्तर की वार्ता हो चुकी है। इस मामले में तमाम असहमति के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार वार्ता कर चुके हैं। ऐसा कोई संयोग नहीं है। अमेरिका यह जानता है कि दक्षिण चीन सागर एवं हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए भारत बेहद उपयोगी है। चीन पर नकेल लगाने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। हाल के दिनों में अमेरिका के लिए भारत की सामरिक उपयोगिता बढ़ी है। क्वाड के गठन को इसी कड़ी में जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा ताइवान भी एक बड़ा फैक्टर है, जहां चीन और अमेरिका आमने-सामने हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहा है। यूक्रेन जंग में वह भारत की नीतियों के विरोध के बावजूद भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की अहमियत की एक वजह यह भी है कि भारत जनवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है। ऐसे में सभी देश चाहते हैं कि भारत अगर उनका साथ न दे तो कम से कम विरोध भी न करे। इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर एवं सक्षम देश है। भारत दुनिया के सबसे प्रमुख बाजारों में से है, यानी बड़े देशों के फायदे के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका समेत सभी ताकतवर देश भारत को अपने पाले में रखना जरूरी मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-अमेरिका के संबंध बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। अगर भारत अमेरिका के व्यापार पर नजर डाले तो दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2019 तक 146 अरब डॉलर यानी करीब दस लाख करोड़ रुपए का था। यह भारत रूस के व्यापार का करीब 15 गुना है। अमेरिका के बाद रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। भारत की हथियार खरीद में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 14 फीसद है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार 21 अरब डॉलर यानी 1.56 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।

भ्रष्टाचार पर आप का अंदाज काबिल-ए-तारीफ

(त्वरित टिप्पणी)

अब इसे शुक्राना कहें या नजराना, धन्यवाद या फिर रिश्वत कोई शक नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उससे मुक्ति की आशा आम आदमी को एक सपने जैसे लगती है। लेकिन बीच-बीच में कोई घटना (यही कहना बेहतर होगा) उम्मीद की लौ बुझने नहीं देती है। लगने लगता है कि कभी न कभी तो इससे निजात मिलेगा? ऐसा ही कुछ भरोसा पंजाब के सेहत मंत्री डॉ. विजय सिंगला की बरखास्तगी और गिरफ्तारी के बाद सींखचों के पीछे पहुँचा देने से बुझी-बुझी सी आस देश में बरकरार जरूर है। क्या कह सकते हैं कि यह बर्खास्तगी एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी बांकी है?

सवाल फिर वही कि आखिर कब तक सिस्टम के रूप में भले ही बेमन से भ्रष्टाचार को स्वीकारा जाता रहेगा? बातें तो खूब होती हैं परन्तु धरातल पर सच्चाई अलग दिखती है। ऐसे में अगर कहीं कोई उदाहरण सामने आ जाए तो जबरदस्त राहत देती नई लकीर बनती है। स्वाभाविक है किसी सरकार की तरफ से कोई कठोर कदम उठाया जाता है तो सबका ध्यान बरबस खिंच जाता है और इस पर बिना लाग लपेट प्रतिक्रियाएँ भी स्वाभाविक हैं। भगवन्त मान न केवल देश के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए बल्कि पहले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल भी उसी पार्टी से हैं। अब पंजाब की सरहद से बाहर यह मसला पूरे देश और दुनिया में जबरदस्त सुर्खियों में है और लोग आश्चर्य, अविश्वास के साथ बहुत बड़े नैतिक कदम के रूप में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की कमर पर प्रहार भी मान रहे हैं। फिलाहाल तो पंजाब में जैसे हर कहीं सनाका खिंच गया है, लोगों को विश्वास तक नहीं हो रहा है और तो और सत्ताधारी दल के लोग, नुमाइन्दें और नौकरशाह बुरी तरह डरे हुए हैं। विरोधियों की गत समझी जा सकती है। बस देखना यही है कि तमाम राजनीतिक नफा-नुकसान के हिसाब-किताब से इतर उठाया गया यह दुस्साहसी कदम 2022 का अकेला उदाहरण बनकर रह जाता है या आगे भी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे तक सिस्टम पर जारी रहेगा?

आम आदमी पार्टी शायद ऐसे उदाहरणों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। हो सकता है उसका शगल हो लेकिन नैतिकता व ईमानदारी के नाम पर उठाया गया यह कदम लोगों को तो खूब भा रहा है। हाँ, पंजाब की नई-नई सरकार के नए सेहत मंत्री को महज 62 दिनों में ही एक झटके में सबूतों के बिना पर बरखास्त कर गिरफ्तार करवा देना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी इच्छा शक्ति और जबरदस्त कशमकश के बाद काफी सोच, समझकर लिया गया फैसला होगा। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि देश में शासन-प्रशासन में सुधार और राहत को लेकर आम आदमी की अभी उम्मीदों की लौ बुझी नहीं है। एक छोटे से दल से ही हुई शुरुआत का बीज खूब फले-फूले। फिलाहाल यह शुकून की बात है।

भारत में भ्रष्टाचार पर अनवरत चर्चाओं का सिलसिला और विरोध में आन्दोलनों की बाढ़ अनवरत चलती रहती है। लेकिन क्या इस पर कभी काबू पाया जा सका? उत्तर को लेकर कोई निरुत्तर नहीं है, सब जानते हैं कि नहीं। दरअसल भ्रष्टाचार का दीमक स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुन जैसे घुस गया जिसको लाख उपचार के बाद भी नहीं खत्म किया जा सका। देखते ही देखते भ्रष्टाचारी ऑक्टोपस बिना मरे टूट-टूट कर ऐसा फैलता रहा कि स्वतंत्रता के दशक भर भीतर ही संसद में बहस होने लगी। संसद का एक महत्वपूर्ण वाकया आज भी प्रासंगिक है जब 21 दिसंबर 1963 को डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच का संबंध भारत में जितना भ्रष्ट और दूषित हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। इसकी जड़ों को लेकर डॉ. लोहिया की उस समय की पीड़ा को 59 सालों के बाद आज भी समझा जा सकता है। इसकी कल्पना मात्र से ही सिरहन हो उठती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस दुस्साहस को राजनीतिक रूप से भले ही कुछ भी समझा जाए लेकिन पुराने कई उदाहरण देखकर लगता है कि डॉ. लोहिया के चिन्तन को सार्वजनिक जीवन के अमल में लाने के लिए कुछ तो हो रहा है।

दरअसल भ्रष्टाचार एक चेन के रूप में गहरे तक घुसपैठ बना चुका है। कहीं न कहीं तमाम विभागों में एक टाईअप जैसे काम करता है। नेता और नौकरशाह इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें न लाज है न भय। अर्थव्यवस्था और हरेक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव डालने वाला रिवाज जो बन गया है। राजनीति, नौकरशाही में के अनगिनत उदाहरण हैं लेकिन न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस भी अछूती नहीं है। विडंबना, मजबूरी या जो भी कुछ कहें, पूरी तरह गैर कानूनी होने के बाद भी रोजाना के चलन में बेखौफ जारी है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इससे न गुजरा हो?

भारतीय इतिहास में दूसरी बार एक मुख्यमंत्री ने सीधे अपने मंत्री पर कार्रवाई की। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटा चुके हैं उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बरखास्त कर सीबीआई जाँच तक करवा दी। उन पर 6 लाख रुपयों की घूस का आरोप था। अपनी जीरो टॉलरेन्स पार्टी का हवाला देकर सितम्बर 2016 में भी केजरीवाल ने महिला एवँ बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को एक कथित आपत्तिजनक सीडी उजागर होने के बाद बरखास्त किया था।

भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी यानी एंटी करप्शन वॉचडॉग की रिपोर्ट-2021 में भारत दुनिया में 180 भ्रष्टों की सूची में जरूर 86 से खिसक 85 पर आ गया और 40 अंकों के साथ 85वां स्थान मिला। कहने की जरूरत नहीं कि माजरा क्या है। काश पूरे देश में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने की बातें सिर्फ भाषणों और किताबों में नैतिकता के रूप में बताई और दिखाई न जाकर धरातल पर उतरतीं! इन्हीं डॉ. विजय सिंगला ने 23 मार्च को कहा था कि वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का दावा भी ठोंका। लेकिन ठीक 62 दिन बाद 24 मई को भ्रष्टाचार के मामले में धर लिए गए।

तमाम आँकड़ों और सबूतों के बावजूद हर साँस में भ्रष्टाचार की बदबू को स्वीकारने की मजबूरी रिवाज सा बन गई है। ऊँचे पदों पर बैठे लोगों से लेकर दरवाजे पर बैठा चपरासी तक कहीं न कहीं इस कड़ी का हिस्सा होता है। चाहे सरकारी राशन दूकानें हो, खनन, परिवहन, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीपीएल कार्ड, विभिन्न योजनांतर्गत आवास, समाज कल्याण, धर्मार्थ कार्य, कफन-दफन का मसला हो या कोई भी सरकारी योजना या शायद ही कोई ऐसा विभाग अछूता हो जहाँ भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का साया न हो। लेकिन सोचना भी भारी पड़ता है कि आखिर क्यों और कब तक? लगता नहीं कि माफिया शब्द भ्रष्टाचार का पर्यायवाची जो बन गया है?

हैरानी की बात है कि तमाम तकनीकी संसाधनों, मुखबिरों, ठोस सबूतों और दावों-प्रतिदावों के बीच भी भ्रष्टाचार तेजी से फल-फूल रहा है? काश दिन, रात, सोते, जागते भ्रष्टाचार को कोसने वाले नेता, नौकरशाह ही इससे मुक्त हो पाते और सोचते कि यह देश तथा भारत माता के माथे पर कलंक और गद्दारी है? बेशक आम आदमी पार्टी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया है और इसके सियासी मायने चाहे जो लगाए जाएँ बस इंतजार है तो इतना कि यह सिलसिला रुके नहीं और दूसरों के उदाहरण भी सामने आएँ। (लेखक- ऋतुपर्ण दवे/ ईएमएस)

मानसून की दस्तक - सरकारी योजनायें - डूबते शहर

उत्तर भारत में मानसून दस्तक देने जा रहा है। निश्चित रूप से जो लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से त्राहि त्राहि कर रहे हैं उन्हें वर्षा ऋतु से होने वाले मौसम परिवर्तन के बाद होने वाले तापमान में गिरावट से काफ़ी राहत महसूस होगी। परन्तु प्रकृति प्रदत्त यही राहत प्रायः उस समय मानव संकट में भी बदल जाती है जबकि मानसून में होने वाली यही बारिश इंसानों को सुकून व राहत देने के बजाये उसकी परेशानी,तबाही व बर्बादी का कारण बन जाती है। देश के कई राज्य आज भी ऐसे हैं जहाँ सरकार चाहते हुये भी बाढ़ के प्रकोप से इंसान व उसे होने वाले नुक़्सान को नहीं बचा पाती है। मानसून शुरू होते ही विभिन्न राज्यों की अनेक उफ़नती हुई नदियां प्रत्येक वर्ष मानवीय तबाही का नया इतिहास लिखती हैं। कहीं पुल बह जाते हैं ,कहीं बाँध टूट जाते हैं,कहीं पूरे के पूरे गांव बाढ़ की विनाशलीला की भेंट चढ़ जाते हैं। हम प्रत्येक वर्ष ऐसा हालत से जूझने के लिये मजबूर रहते हैं तथा इसे प्रकृतिक बाढ़ प्रकोप या इससे उपजी विनाश लीला समझकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि इसतरह की अनियंत्रित बाढ़ में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा कारक होता है। मिसाल के तौर पर नदियों के किनारे बनने वाले बांधों के निर्माण में बड़े पैमाने पर होने वाला भ्रष्टाचार,अवैध खनन, कमज़ोर पुलों व पुलों के खम्बों का घटिया स्तर का निर्माण आदि। परन्तु बाढ़ के प्रकोप को 'प्रकृतिक प्रकोप' मानकर सरकार स्वयं को किसी तरह की ज़िम्मेदारी से बचा ले जाती है।

परन्तु शहरी इलाक़ों के डूबने की ज़िम्मेदार जहां मानवनिर्मित अनेक समस्यायें हैं वहीं सरकार की ग़लत योजनायें भी इसके लिये कम ज़िम्मेदार नहीं। उदाहरण स्वरूप शहरों में बनाई या मरम्मत की जाने वाली गलियां बार बार ऊँची से ऊँची की जाती हैं। और उनके दोनों तरफ़ की नालियों की गहराई को कम कर उसे और छिछला कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक मकानों का मुख्य स्तर गलियों व सड़कों से भी नीचे हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश का पानी मकानों में प्रवेश कर जाता है। और अगर बारिश तेज़ हो फिर तो गली मोहल्लों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। उधर हरियाणा के अंबाला जैसे विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में बरसाती तथा नालों के माध्यम से जल निकासी हेतु अनेक नये नालों का निर्माण किया गया है। इसी तरह प्रायः फ़्लाई ओवर्स के नीचे भी नाले बनाये गये हैं। आज यदि पूरी ईमानदारी के साथ इन नवनिर्मित नालों की स्थिति पर नज़र डाली जाये तो यह अधिकांश जगहों पर न केवल क्षति ग्रस्त मिलेंगे बल्कि ज़्यादातर नाले अवरुद्ध भी नज़र आयेंगे। तमाम जगहों पर यह नाले नालियां पूरी तरह ढके होंगे। इतने ढके कि इनकी न तो सफ़ाई की जा सकती है न ही इनमें जमे कीचड़ मलवे को निकाला जा सकता है। गोया सरकार, निर्धारित योजनानुसार निर्माण तो कर देती है। परन्तु उसे सुचारु रूप से प्रवाहित करने की ओर ध्यान नहीं देती। यदि करोड़ों रूपये ख़र्च करने के बावजूद नालों व नालियों से गन्दा पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है और बजाये इसके यही नाली नाले शहरों में आने वाली बढ़ का कारण भी बने फिर जनता के पैसों की बर्बादी का आख़िर क्या औचित्य है ?

शहरों के डूबने में सरकार के साथ साथ जनता भी कम दोषी नहीं है। जो गंदे नाले व नालियां गंदे घरेलू पानी या वर्षा जल को प्रवाहित करने के लिये होते हैं उन्हीं नालों में आपको मरे हुये जानवर,रज़ाई,गद्दे,कंबल,कपड़े,कांच व प्लास्टिक की बोतलें पॉलीथिन,प्लास्टिक,ईंट-पत्थर,जूते चप्पल,घरेलु कूड़ा करकट आदि न जाने क्या क्या पड़ा नज़र आयेगा। ज़ाहिर है यह 'कारगुज़ारी' सरकार की नहीं बल्कि आम लोगों की है। हमारी और आप की है। हमें यह समझना होगा कि हम नालियों का इस्तेमाल केवल गंदे जल के प्रवाह करने के मक़सद तक ही करें। इन्हें हम कूड़ा घर क़तई न बनने दें। हम स्वयं भी ऐसा न करें और यदि कोई ऐसा करते दिखाई दे तो उसे भी मना करें। इन्हीं लापरवाहियों के चलते बरसात के दिनों में शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और जो लोग नालों व नालियों को कूड़ाघर बनाते हैं उन्हीं के मकानों में वर्षा जल नालों के गंदे पानी के साथ प्रवेश करता है जोकि परेशानी व असुविधा के साथ साथ विभिन्न बीमारियों को भी दावत देता है।

इसके साथ साथ सरकार का भी कर्तव्य है कि वह युद्धस्तर पर शहरी नालों व नालियों की समुचित सफ़ाई करवाये। टूटे फूटे नालों व नालियों की मरम्मत कराये। इनमें जमी गाद व कचरा कूड़ा आदि पूरी तरह साफ़ करवाकर नाले नालियों के पानी की प्रवाह पूर्ण स्थिति सुनिश्चित करे। जिन लोगों ने अपनी सुविधानुसार अथवा सरकारी ठेकेदारों द्वारा नालों को इतनी दूर तक ढक दिया गया है कि उसके नीचे सफ़ाई कर पाना ही संभव नहीं,नालों के ऐसे ढके हिस्से को तुड़वाकर इन्हें खोलने की व्यवस्था की जाये ताकि सफ़ाई कर्मचारी सुगमता से इनकी सफ़ाई कर सकें। वर्तमान मशीनी युग में ऐसे नालों नालियों की सफ़ाई के लिये भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नालों व नालियों का निर्माण या इनकी मरम्मत स्तरीय होनी चाहिये। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ऐसी योजनाएं भी जहाँ बाढ़ का कारण बनती हैं वहीं नालियों की गुणवत्ता की कमी से लोगों के घरों में भी नाले नाली के पानी का रिसाव होता है। इसकी वजह से मकान की नींव तो कमज़ोर होती ही है साथ ही घरों में सीलन भी पैदा होती है।

गली निर्माण व मुरम्मत के लिये भी सरकार स्पष्ट निर्देश जारी करे कि कोई भी गली पुरानी गली को खोद कर गली के उसी स्तर पर तैय्यार की जाये जो स्तर पूर्व में था। और यदि कोई ठेकेदार किसी गली को नये स्तर पर ऊँचा करता है इसका अर्थ है कि वह भ्रष्ट है और शहरवासियों को संकट में डालना चाहता है। ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाये और यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत से वह ऐसा कर रहा हो तो उस अधिकारी को भी पदमुक्त किया जाना चाहिये। यदि समय रहते सरकार ने नालों व नालियों की समुचित सफ़ाई नहीं करवाई तो मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और निःसंदेह बिना रखरखाव वाली यही ग़लत सरकारी योजनायें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की वर्षा ऋतू में भी डूबते हुये शहरों का करक बन सकती हैं। (लेखक- निर्मल रानी/ ईएमएस)

भारत निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है पंडित नेहरू का!

(पुण्यतिथि पर)

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। वे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हो ,उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विश्व के बारे में जानकारी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित होते थे और इसीलिए आज़ादी के बाद वह उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे।महात्मा गांधी के ही प्रयास से वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन पाए। सन् 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया था। सन 1923 में पंडित नेहरु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव चुने गए।सन 1952 में देश मे पहले आमचुनाव हुए ,जिसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इससे पहले वह सन1947 में आज़ादी मिलने के बाद से अंतरिम प्रधानमंत्री थे। संसद की 497 सीटों के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए थे। लेकिन जहाँ संसद में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ ,वहीं कुछ राज्यों में कांग्रेस को दूसरे दलों से ज़बर्दस्त टक्कर मिली थी। कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करने में चेन्नई, हैदराबाद और त्रावणकोर जैसे शहरों में विफल रही थी, उसे कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी। हालाँकि इन चुनावों में हिन्दू महासभा और अलगाववादी सिक्ख अकाली पार्टी को मुँह की खानी पड़ी थी। पहले चुनाव के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने दक्षिणी राज्यों में जनसमर्थन बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे सन 1957 में हुए चुनाव में उसे मिले। त्रावणकोर-कोचिन और मालाबार को मिला कर बने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई।सन

1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्षों तक यानि सन 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पंडित नेहरू ने देश में विकास पटरी बिछाई थी , सन1962 में चीन से हारने के बावजूद, नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी जी वस्तुतः सामाजिक उदारवादी थे, जो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्ठा कर रहे थे। नेहरु लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे। वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे।देश के इतिहास में एक ऐसा अवसर भी आया था, जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ़ इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान् राजनीतिज्ञ , प्रभावशाली वक्ता ही नहीं, प्रसिद्ध लेखक भी रहे। उनकी आत्मकथा सन 1936 ई. में प्रकाशित हुई थी। उनकी अन्य पुस्तकों में भारत एक खोज, भारत और विश्व, सोवियत रूस, विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की एकता और स्वतंत्रता और उसके बाद उल्लेखनीय हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगीकरण को महत्व बहुत महत्व दिया। भारी उद्योगों की स्थापना को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास के लिए सन1947 ई. में नेहरू ने 'भारतीय विज्ञान कांग्रेस' की स्थापना की। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। खेलों में नेहरू की खास रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया था। एक देश का दूसरे देश से मधुर सम्बन्ध क़ायम करने के लिए सन 1951 ई. में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कराया था। नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा था। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया। वे सन 1938 ई. में कांग्रेस द्वारा नियोजित 'राष्ट्रीय योजना समिति' के अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वे 'राष्ट्रीय योजना आयोग' के प्रधान बने। नेहरू के व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था।जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुटता एवं पंचशील जैसे सिद्धान्तों का पालन कर विश्व बन्धुत्व एवं विश्वशांति को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद एवं उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ जीवनपर्यन्त संघर्ष किया। अपने क़ैदी जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया', 'ग्लिम्पसेज ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री' एवं 'मेरी कहानी' नामक पुस्तकों की रचना कर स्वयं को एक लेखक के रूप में भी सिद्ध किया।उनको बच्चे बहुत प्रिय रहे,बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के रूप में सम्मान देते थे।तभी तो उनका जन्मदिन बालदिवस के रूप में मनाया जाता है।

चाचा नेहरू अब आ भी आओ
हमको अच्छे खिलौने दिलाओ
समय अब बहुत बदल गया है
बच्चों का भी खेल बदल गया है
गिल्ली डंडा ,कबड्डी नही रहे अब
कुश्ती,खो खो इतिहास हो गए अब
सब पर क्रिकेट का जुनून सवार है
मोबाईल खेल का बड़ा हथियार है
सांप सीडी लूडो से नही प्यार है
कार्टून फिल्मे ही हमे भाती है
कम्प्यूटर गेम खूब लुभाती है
गुलाब का फूल अब नही लेंगे
मिठाई भी पसन्द हम नही करेंगे
चावमीन, पिज्जा अच्छा लगता है
चॉकलेट, बर्गर हमे बहुत भाता है
बाल कल्याण की कोई नीति नही है
हमे लुभाने की कोई रीति नही है
चाचा नेहरू सिर्फ तुम्ही थे अपने
तुम्हारे बिन हमारे ध्वस्त है सपने
आज के नेताओं को सद्बुद्धि दे दो
बालदिवस पर एक छुट्टी दिला दो।

(लेखक -डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट / ईएमएस)

आज का इतिहास 27 मई

1897 कॉपी राईट विधेयक पारित हुआ.
1905 जापानियों ने कोरिया के पास समुद्र में रूस के 32 जहाजों के बेड़े को तबाह कर दिया.
1916 प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन फौजों ने पश्चिमी मोर्चे पर जवाबी कार्यवाही की.
1941 द्वितीय विश्वयुद्ध में फ्रांस के समुद्र में जर्मन युद्धपोत को 2300 व्यक्तियों सहित ब्रिटिश नौसेना ने डुबो दिया.
1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन.
1971 सोवियत संघ ने मिस्त्र के साथ 15 वर्षीय समझौता किया.
1990 अमरीका ने पश्चिमी देशों के विचार विमर्श के बिना यूरोप से अपनी फौजे हटाने से इंकार किया.
1991 कुवैत में विपक्षी नेताओं ने मार्शल ला हटाने की मांग की.
1992 पटियाला आकाशवाणी के इंजीनियर एम.एल.मनचंदा की हत्या.
1994 बीस वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद एलेक्जैंडर शोल्जेनित्शिन रूस लौटे.
1999 घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय भारत के दो हवाई जहाज गिरे. एक पायलट को पाकिस्तान के सैनिको ने मार डाला जबकि दूसरे को युद्धबंदी बना लिया गया.
1999 कांग्रेस से निष्कासित शरद पवार, तारिक अनवर व पी.ए.संगमा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई.
2002 भारत की जवाबी गोलाबारी में 11 पाकिस्तानी सैनिक मरे.
2005 सोनिया गांधी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुनः अध्यक्ष चुन ली गई.

शब्द पहेली - 7298

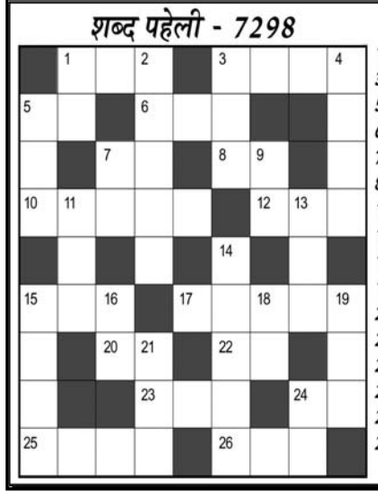

बाएँ से दाएँ

1.कंठ,गला-3
3.पक्षियों का शौर-4
5.शारीरिक ऊँचाई-2
6.पाचन शक्ति-3
7.मां की माता-2
8.प्यार,प्रेम(अंग्रेजी-2)
10.रचना करने वाला-5
12.शोरबा,तरी-3
15.खाद्य सामग्री-3
17.दोनों हाथों को पीटना-5
20.भाग्य(अंग्रेजी-2)
22.कदली,एक फल-2
23.उपासना,शीश झुकाना-3
24.घ्राणेन्द्रिय,नासिका-2
25.तहखाना-4
26.दया-3

ऊपर से नीचे

1.मर्यादा,सीमा-2
2.कहानी लिखने वाला-5
3.अचरज भरा कार्य-3
4.वर,इच्छित वस्तु देना-4
5.जलजला-3
7.मां के पिता-2
9.चिकनाई-2
11.हशीश,एक प्रकार का मादक पदार्थ-3
13.बोलने का तरीका-3
14.तमीजवाला-5
15.परंपरा,रिवाज-4
16.राजनीतिक पार्टी-2
18.आफत,मुसीबत-2
19.नाट्य,कथा मंचन-3
21.कमी-3
24.संबोधन-2

शब्द पहेली - 7297 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

सानिया- डोडिग मिश्रित युगल के दसरे दौर मे पहुंचे

पेरिस (ईएमएस)। भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के इवान डोडिग फ्रैंच ओपन टेनिस के मिश्रित युगल मैच के दूसरे दौर में पहुंच गये हैं। सानिया और डोडिग की जोड़ी ने पहले दौर में जर्मनी की लॉरा सिगमंड और मेक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज को 7-6(4), 6-2 से सीधे सेटों में हराया।

इस जीत के साथ ही सानिया-इवान की जोड़ी फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। सानिया इस क्ले-कोर्ट ग्रैंड स्लैम में आखिरी बार खेल रही हैं क्योंकि उन्होंने इस सत्र के बाद खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। वहीं युगल मुकाबले में सानिया अपनी चेकोस्लोवाकिया की साथी खिलाड़ी लुसी ह्राडेका के साथ पहले दौर में इटली की जासमीन पाओलिनी और माटिर्नी ट्रेविसान से खेलेंगी।

दूसरे क्वालीफायर में आज आरसीबी और रॉयल्स में होगी टक्कर

अहमदाबाद (ईएमएस)। आईपीएल के 15 वें सत्र में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की टीम दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर जीत के इरादे से उतरेगी। लखनऊ जाइंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में मिली जीत से आरसीबी उत्साहित है और अब उसका लक्ष्य खिताबी मुकाबले में जगह बनाना रहेगा। वहीं दूसरी ओर पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस से मिली करीबी हार को भुलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने उतरेगी। ऐसे में इस मैच के रोमांचक होने के आसार हैं क्योंकि दोनो ही टीमें जीत के लिए अपना सर्वश्रेष

महंगाई के बढ़ते ग्राफ ने तीन महीने में बढाया 10 फीसदी घर का खर्च

नई दिल्ली (ईएमएस)। बेतहाशा भड़ती महंगाई ने आम आदमी का जीवन जीना दूभर कर दिया है। ताजा सर्वे में पता चला है कि आम आदमी के रोजमर्रा खर्चों में हर महीने 10 फीसदी का इजाफा हो चुका है। यह बढ़ोतरी पिछले तीन महीने में हुई है। मनीकंट्रोलकी खबर के मुताबिक, लोकल सर्किल ने हाल में देश के 323 जिलों में 12 हजार से अधिक घरों में एक सर्वे किया। इस सर्वे से मिले 23,500 लोगों के रिस्पांस से पता चला है कि पिछले तीन महीने में ही घर का खर्च 10 फीसदी बढ़ गया है। सर्वे में शामिल 10 में से 7 लोगों का कहना है कि उनके घर का खर्च तीन महीने के भीतर बढ़ गया है। इस दौरान औसत कीमत 15 फीसदी की दर से बढ़ी है।

सर्वे में शामिल लोगों ने इस बात की भी आशंका जताई कि आगे भी महंगाई और झटके देगी। 55 फीसदी लोगों ने कहा, महंगा पेट्रोल-डीजल अभी राहत नहीं लेने देगा और आने वाले तीन महीने में घर का खर्च फिर 10 फीसदी बढ़ सकता है। सर्वे में शामिल लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी बचत भी खत्म हो रही है और आगे भी आमदनी बढ़ने से पहले खर्चों का बोझ बढ़ता दिख रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ दुनियाभर में चल रही भूराजनैतिक तनावों की वजह से कई तरह की कमोडिटी की सप्लाई पर असर पड़ा और घरेलू बाजार में भी कीमतों में वृद्धि हुई। इसका सीधा असर आम आदमी के खर्चों के साथ इकॉनमी पर भी दिख रहा है। यही कारण है कि 55 फीसदी लोगों ने आगे भी महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि अगले तीन महीने में फिर घर का खर्च 10 फीसदी बढ़ सकता है। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें जनता को राहत देने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रहे हैं। इस कड़ी में ही हाल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इससे महंगाई से त्रस्त जनता को काफी राहत मिली है। हालांकि, उपभोक्ता आधारित खुदरा महंगाई की दर अप्रैल में बढ़कर 7.79 फीसदी पहुंच गई है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी आई। बाजार में यह उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में आई बढ़त से आया है। इसी के साथ ही बाजार में पिछले दिनों से जारी गिरावट थम गयी। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 503.27 अंक करीब 0.94 फीसदी बढ़कर 54,252.53 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144.35 अंक तकरीबन 0.90 फीसदी ऊपर आकर 16,170.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, नेस्ले, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा के शेयरों ऊपर आये जबकि सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो और डॉ. रेड्डीज के शेयरों में गिरावट आई

कारोबार के दौरान टाटा स्टील , जेएसडब्ल्यू स्टील , अपोलो हॉस्पीटल, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के शेयरों को लाभ हुआ जबकि वहीं आईटीसी, यूपीएल, डिविस लैब्, सन फार्मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को नुकसान हुआ।

वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ के साथ बंद हुआ जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान के निक्की में गिरावट आई है। दूसरी ओर यूरोप के बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे जबकि अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

सोने का भाव टूटा, चांदी भी हुई सस्ती

नई दिल्ली (ईएमएस)। वै?श्विक बाजारों में कीमती धातुओं में नरमी की वजह से एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने की कीमत में 0.04 फीसदी की गिरावट आई और इसका भाव टूटकर 50,800 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया है। वहीं चांदी का भाव भी 0.16 फीसदी टूट गया। इस कमी के बाद चांदी की कीमत कम होकर 61,437 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। यहां बता दें कि आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है।

बढ़ी मंहगाई में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश कम

नई दिल्ली (ईएमएस)। मौजूदा महंगाई और कीमतों की स्थिति के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश काफी कम है। मामले से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में अभी चार टैक्स स्लैब, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। यानी, इन दरों के हिसाब से अलग-अलग चीजों पर टैक्स लगाता है। लेकिन, अभी इन टैक्स स्लैब को घटाकर संभवतः तीन करने पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है, तब कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा, जबकि कुछ पर कम होगा। वहीं, सोने और सोने के आभूषणों की बात करें तब इन पर तीन प्रतिशत टैक्स लगता है।

लेकिन सूत्रों ने कहा है कि मंहगाई दर ज्यादा है। इसके बाद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश कम है। सूत्रों ने कहा कि जहां अर्थव्यवस्था 2021 में कोविड के प्रभाव से उबर रही थी, वहीं इस साल फिर से भू-राजनीतिक तनाव का असर इस पर पड़ेगा। सूत्र ने कहा, ''पूर्व में जीएसटी परिषद तत्कालीन स्थितियों से बेखबर नहीं थी।''

जीएसटी के तहत अभी आवश्यक वस्तुओं को या तब सबसे कम स्लैब में रखा गया है या फिर टैक्स से बाहर रखा गया है जबकि लग्जरी और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर उच्चतम स्लैब (28 प्रतिशत) लागू होता है। जीएसटी लागू होने से राज्यों के संभावित राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उपकर भी लगाया जाता है। जीएसटी परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था, जो कर दरों को तर्कसंगत बनाकर और कर दरों में विसंगतियों को दूर करके राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाएगा। इससे पहले 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के समय, केंद्र ने राज्यों को जून 2022 तक 5 साल के लिए कम्पनसेट करने और 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उनके राजस्व की रक्षा करने पर सहमति व्यक्त की थी।

सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली शुरू की

नई दिल्ली (ईएमएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसमें 201 प्रकार के कागज और टिशू पेपर समेत पेपर बोर्ड शामिल हैं। मंत्रालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत आयातकों को इन कागज के आयात के बारे में पहले से ऑनलाइन जानकारी देनी होगी और पंजीकरण संख्या लेनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अध्याय 48 के तहत कुछ वस्तुओं के मामले में आयात नीति संशोधित की गई है। इसके तहत पीआईएमएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि आयातक आयात खेप आने की संभावित तिथि से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों तक वैध रहेगी। पीआईएमएस एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।

देश में 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकता है पाम ऑयल का आयात

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत का पाम ऑयल आयात 19 फीसदी गिरकर 11 साल के सबसे निचले स्तर पर आ सकता है। इसका कारण यह है कि सोया तेल अब सस्ता है। साथ ही, इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी और सरकार की सोया ऑयल के ?निशुल्क आयात? की अनुमति के कारण सोया ऑयल की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े खाने के तेल के आयातक की ओर से पाम ऑयल की खरीदारी घटाने से मलेशियाई पाम ऑयल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। भारत सोया ऑयल के आयात के रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के साथ अमेरिकी सोया ऑयल वायदा कीमतों को समर्थन दे सकता है। पांच डीलरों के औसत पूर्वानुमान के हवाले से रिपोर्ट के मुता?बिक 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाले मार्केटिंग वर्ष 2021-22 में भारत का पाम ऑयल आयात घटकर 6।7 मिलियन टन रह सकता है, जो 2010-11 के बाद सबसे कम होगा। इस साल सोया ऑयल का आयात एक साल पहले के मुकाबले 57 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 45 लाख टन पर पहुंच सकता है।

एक जून से थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ेगा

- एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली ?निजी कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपए होगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की है जो एक जून से लागू होगी। इससे कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली ?निजी कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा जो वर्ष 2019-20 में 2072 रुपये था। इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए अब 3221 रुपये के बजाय 3416 रुपये प्रीमियम देना होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कमी की गई है और यह 7,897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपये होगा जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपये होगी। 1000 सीसी से कम क्षमता वाली नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये होगा जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए यह 10,640 रुपये होगा। 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली नई कारों के लिए तीन साल का प्रीमियम 24,596 रुपये होगा।

इसी तरह 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2901 रुपये, 75 सीसी से 150 सीसी तक क्षमता वाले वाहनों के लिए 3,851 रुपये तथा 150 सीसी और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 7,365 रुपये होगा। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये होगा। 30 केडब्ल्यू तक के नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक वीकल के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 5,543 रुपये का होगा। 30 केडब्ल्यू से 65 केडब्ल्यू अधिक क्षमता वाले ईवी के लिए यह 9,044 रुपये होगा। बड़े ईवी के लिए तीन साल का प्रीमियम 20,907 रुपये होगा। तीन केडब्ल्यू तक के नए दोपहिया ईवी वाहनों का पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2,466 रुपये होगा। इसी तरह तीन से सात केडब्ल्यू तक के दोपहिया ईवी वाहनों का प्रीमियम 3,273 रुपये और सात से 16 केडब्ल्यू तक का प्रीमिय 6,260 रुपये होगा। ज्यादा क्षमता वाले ईवी दोपहिया वाहनों का पांच साल का प्रीमियम 12,849 रुपये होगा।

नया वाहन खरीदने के साथ ही वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। थर्ड पार्टी बीमा को लाइबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। अगर किसी ने वीकल का थर्ड पार्टी बीमा कराया है और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। वाह की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान

अफ्रीकी देश सेनेगल में अस्पताल में आग लगने से 11 नवजात की मौत

तिवाउने (ईएमएस)। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के तिवाउने में एक अस्पताल में आग लगने से 11 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यहां की एक समाचार एजेंसी ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल के हवाले से ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति मैकी सैल के हवाले से कहा गया ?कि मैंने अभी-अभी एक बेहद दुखद और निराशाजनक खबर सुनी। तिवाउने के एक सार्वजनिक अस्पताल में नवजात विभाग में आग लगने से 11 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। ये हादसा देर रात हुआ। मैं मासूमों की माताओं और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।सेनेगल के राजनेता डीओप सी के अनुसार, यह त्रासदी तिवाउने के परिवहन केंद्र में मामे अब्दौ अजीज सी दबाख अस्पताल में हुई थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि वह आग लगने की वजहों की जांच कर रही है। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आग कहां से उठी। सेनेगल के इतिहास में यह अबतक की सबसे बड़ी आग लगने की घटना में से एक है। पिछले साल भी सेनेगल में एक अस्पताल के नियोनेटल वार्ड में आग लग गई थी, जिसमे 4 बच्चों की मौत हो गई थी।

ताइवान पर बाइडेन के ऐलान से भड़का ड्रैगन, चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में की बमबारी

बीजिंग (ईएमएस)। ताइवान पर हक जमाने के साथ चीन लगातार दबाव बना रहा है और हमले की धुड़की भी दे रहा है। ऐसे में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका सामने आया है। सेना भेजने के जो बाइडेन के ऐलान से चीन भड़क गया है और उसने दक्षिण चीन सागर में जोरदार युद्धाभ्यास कर बमबारी की है। चीन की सरकार की मीडिया के मुताबिक सेना ने पूर्वी थिएटर कमांड ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया है। इसमें चीनी नौसेना और एयरफोर्स दोनों ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने इस दौरान ताइवान पर कब्जे का अभ्यास किया। चीनी सेना पीएलए के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी ने कहा कि यह अभ्यास अमेरिका को चेतावनी देने के लिए आयोजित किया गया था। इससे पहले बाइडन ने चेतावनी दी थी कि अगर चीनी सेना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना उसका जवाब देगी। हालांकि बाद में वाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर सफाई दी थी और कहा था कि अमेरिका एक चीन नीति में भरोसा करता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और पीएलए का पूर्वी थिएटर कमांड राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्नल शी यी ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुआ चीनी सेना का लाइव फायर ड्रिल अमेरिका और ताइवान के गठजोड़ के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए पाखंड और निरर्थक है कि वह ताइवान के मुद्दे पर कहे कुछ और करे कुछ। इससे पहले क्वाड देशों की जापान की राजधानी टोक्यो में हुई बैठक में ताइवान का नाम लिए बिना ही चीनी हमले को लेकर शी जिनपिंग को चेतावनी दी गई थी। क्वाड देशों ने कहा कि हम यथास्थिति में बदलाव के किसी भी एकतरफा कार्रवाई और तनाव बढ़ाने का हम जोरदार विरोध करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमिओ किशिदा ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को हिला रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत कहीं भी एकतरफा यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास को सहन नहीं करेंगे। क्वाड देश जब यह बैठक कर रहे थे, ठीक उसी समय चीन और रूस के परमाणु बॉम्बर ने जापान की हवाई सीमा के बेहद करीब से उड़ान भरी। इसके जवाब में जापान ने भी अपने फाइटर जेट को उड़ाया और पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ गया।

नासा के 'भरोसेमंद' हबल टेलिस्कोप ने खींची व्हर्लपूल गैलेक्सी की आकर्षक तस्वीर, लोगों ने तारीफ

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलिस्कोप ने अपने 30 साल के करियर में कई दिलचस्प घटनाओं की तस्वीरें खींची हैं। हबल के कैमरे में ब्रह्मांड के कुछ सबसे आश्चर्यजनक नजारे कैद हुए हैं जिसने अंतरिक्ष में लोगों की रुचि को बढ़ाया है। ऐसी ही एक और अद्भुत तस्वीर को नासा ने शेयर किया है, जो हबल के कैमरे में कैद हुई है। नासा ने ट्विटर पर गैलेक्सी एम51 की एक शानदार तस्वीर शेयर की है, जिसे व्हर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जाता है।

नासा ने कैप्शन में लिखा, हम गोल-गोल घूमते हैं, अपने आप को व्हर्लपूल गैलेक्सी के भंवर, गुलाबी तारों और नीले तारों के क्लस्टरों में खो जाने दें। इस 'हिप्नोटिक स्पाइरल गैलेक्सी' को हबल के एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वे ने विजिबल लाइट में कैद किया है। शेयर किए जाने के बाद से नासा के ट्वीट को 10,000 से अधिक लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तस्वीर को देखकर आश्चर्य प्रकट किया है।

एक यूजर ने लिखा काश कोई एआई होता। जो तस्वीरों को समझा पाता और इसे संगीत में बदल देता। मुझे यह सुनना बेहद अच्छा लगेगा कि यह तस्वीर कैसी लग रही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा यह बहुत सुंदर दिख रही है। एक तीसरे ने लिखा, क्या खूबसूरती है, मैं अपनी नजरें नहीं हटा सकता। स्पेस एजेंसी ने बताया कि गैलेक्सी एम51 की सुंदर, घुमावदार भुजाएं वास्तव में तारों और धूल से भरी गैस की लंबी गलियां हैं। हबल टेलीस्कोप पिछले 30 साल से अंतरिक्ष और समय का डेटा इकट्ठा कर रहा है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास दर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अंतरिक्ष बढ़ रहा है। नासा ने कहा कि उनके पास पहले की अपेक्षा अब और अधिक सटीकता है। खगोलविदों के मुताबिक अंतरिक्ष के फैलने की रफ्तार 67.5 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक होनी चाहिए, लेकिन डेटा के अवलोकन से पता चलता है कि यह 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक है।

अमेरिकी स्कूलों के इतिहास में पहला नहीं टेक्सास अटैक, 23 सालों में 9 सिरफिरे 151 लोगों की ले चुके हैं जान

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के टेक्सस में 18 साल के युवक ने रॉब एलिमेंटरी स्कूल में गोलीबारी कर 18 बच्चों समेत 21 लोगों की जान ले ली। बीते पांच सालों में यह सबसे घातक हमला है। अगर इतिहास को देखें, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब अमेरिकी स्कूल या कॉलेज सिरफिरों का शिकार बने हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक सैकड़ों लोग इस तरह घटनाओं में जान गंवा चुके हैं।

कोलोराडो के लिटलटन में दो छात्रों ने हमला कर 12 साथियों की हत्या कर दी थी। उस दौरान एक शिक्षक की भी मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसक घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावरों ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। एक 16 साल के छात्र ने मिनेसोटा के घर पर अपने दादाजी और उनके साथी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने नजदीक स्थित रेड लेक हाईस्कूल का रुख किया और 5 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावर ने खुद को मारने से पहले 5 छात्रों, एक शिक्षक और सिक्युरिटी गार्ड को भी मार दिया था। यहां 23 साल के छात्र ने वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग स्थित परिसर को निशाना बनाया। हमलावर ने खुद को मारने से पहले 32 लोगों की जान ली और 2 दर्जन से ज्यादा को घायल कर दिया था।

कनेटिकट के न्यूटाउन में 19 साल का लड़का 27 लोगों की मौत का कारण बना। यहां हमलावर ने घर पहले अपनी मां की जान ले ली। इसके बाद नजदीकी सैंडी हुक एलिमेंटरी में जाकर 20 छात्रों और 6 शिक्षकों को मारा। इसके बाद आरोपी ने भी अपनी जान दे दी। ओरिगॉन के रोजबर्ग में एक व्यक्ति ने खुदकुशी से पहले 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 9 अन्य को घायल कर दिया था। फ्लोरिडा के पार्कलैंड स्थित स्कूल में हुए हमले में 14 छात्रों की जान चली गई थी। इस हमले में स्टाफ के 3 लोगों की भी मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

इस मामले में 20 वर्षीय संदिग्ध पर हत्या के आरोप लगे थे। ह्यूस्टन इलाके में मौजूद एक हाईस्कूल में 17 साल के लड़के ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि मरने वालों में अधिकांश छात्र थे। आरोपी पर हत्या के आरोप लगे थे।

विश्व बैंक को आर्थिक मंदी की आशंका, रूस-यूक्रेन जंग बन रही बड़ी वजह

नई दिल्ली (ईएमएस)। विश्व बैंक ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा है कि युद्ध का असर खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और फर्टिलाइजर की आपूर्ति पर पड़ रहा है। इसके चलते वैश्विक मंदी आ सकती है।

संकट को देखते हुए विश्व बैंक ने पहले ही 2022 के अपने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को 1 फीसदी घटा कर 3.2 फीसदी कर दिया है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में डेविड मालपास ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी सुस्त हो गई है। जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वहीं, फर्टिलाइजर के कम उत्पादन से दूसरे देशों के हालात बिगड़ सकते हैं।

डेविड मालपास ने कहा, 'ग्लोबल जीडीपी को देखते हुए अभी यह कहना मुश्किल है कि मंदी से कैसे बच सकते हैं।' युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आने का अनुमान है। वहीं यूरोपीय देश, चीन और अमेरिका की रफ्तार ज्यादा सुस्त हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में उछाल की वजह से विकासशील देशों को ज्यादा मुश्किल हो रही है। विश्व बैंक प्रमुख ने कहा, 'ऊर्जा की कीमतें यदि बढ़ कर दोगुनी हो जाती है तो मंदी को बढ़ावा देने के लिए ये अकेला ही पर्याप्त है। कोविड-19 महामारी, महंगाई और रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों के चलते चीन की ग्रोथ असाधारण रूप से सुस्त हो रही है।'

भारत में कोविड-19 से प्रभावित एमएसएमई कंपनियों की सहायता के लिए विश्व बैंक ने जून 2021 में 50 करोड़ डॉलर की कर्ज योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी एमएसएमई कॉम्पिटीटिवनेस प्रोग्राम के जरिये लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रदर्शन सुधारने में जुटी है। इस योजना का मकसद 5.55 लाख से ज्यादा एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है।

इमरान खान के आजादी मार्च जल उठा इस्लामाबाद, समर्थकों ने मेट्रो स्टेशन फूंका, सरकार ने सेना उतारी

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान में इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद नए पीएम शहबाज शरीफ से भी सत्ता संभलती नहीं दिख रही है। अब हालात सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। इमरान खान चुनाव की मांग को लेकर अपने समर्थकों संग इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान के इस आजादी मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने रेड जोन में सेना की तैनाती भी कर दी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों में झड़प की खबरें भी आई हैं। इमरान के समर्थकों ने वहां एक मेट्रो स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया है। पीटीआई पार्टी के नेता फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान सेंटेरियस ब्रिज पर समर्थकों को संबोधित करेंगे।

इमरान का काफिला स्वाबी वाली से चला था और श्रीनगर हाईवे (पाकिस्तान में) होते हुए डी-चौक पहुंचेगा। उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहले से डी-चौक पर मौजूद हैं, जिनको हटाने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं।पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने समर्थकों के साथ डी-चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता सरकारी बिल्डिंग्स की रक्षा करना है। शहबाज शरीफ की सरकार का कहना है कि इमरान के समर्थक सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, पीएम हाउस, प्रेसिडेंसी, पाकिस्तान सचिवालय और राजनयिक एन्क्लेव को निशाना बना सकते हैं।पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों को रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के कार्यकर्ताओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई सड़कों को ब्लॉक किया गया है।

काबुल में मजार-ए-शरीफ के पास लगातार चार धमाके, 16 की मौत, 22 घायल

काबुल (ईएमएस)। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक बाद एक चार धमाके हुए। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ में यात्री वैन में तीन धमाके हुए। तालिबान के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी कि मस्जिद के पल्पिट में विस्फोट रखे गए थे, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी बल्ख प्रांत में यात्री वैन में हुए तीन विस्फोटों में कम से कम नौ लोगों की मौत हुई है और 15 घायल हुए हैं। बल्ख प्रांत के पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजेरी ने रॉयटर को बताया शिया समुदाय को टारगेट करके हमला किया गया जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। काबुल के एक ?व्य?क्ति का कहना है ?कि हम यहीं पास में थे तभी बहुत जोर से धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी जबरदस्त थी कि हम सब होश खो बैठे। ये धमाका जरकारिया मस्जिद में नमाज के बाद हुआ। लेकिन बहुत लोग मस्जिद के अंदर थे जब हम वहां पहुंचे तो हमने जमीन पर लाशें और कई लोगों को घायल अवस्था में पाया। इसके पहले 21 अप्रैल को मजार-ए-शरीफ की मस्जिद में धमाका हुआ था। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 65 लोग घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी, जो एक इस्लामिक आतंकी संगठन है।

इसी दिन मजार-ए-शरीफ के कुदुंज प्रांत के सरदारवर इलाके में भी धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत और 18 लोग घायल हुए थे। 19 अप्रैल को काबुल के अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल में धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दर्जन भर से अधिक घायल हो गए थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लगातार आतंकी घटना बढ़ गई हैं। लगातार हो रहे धमाके ने तालिबान की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, जिसका टारगेट शिया समुदाय रहता है जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है।

फ्लाइंग कार एयर-वन के लिए ब्रिटेन में तैयार हुआ दुनिया का पहला हवाई अड्डा, ड्रोन भी भरेंगे उड़ान

लंदन (ईएमएस)। कारें भी उड़ सकती है आप से कहा जाए तो आप अतंभित हो जाएंगे क्योंकि आपने अभी तक हवाई जहाजों को उड़ते देखा है। लेकिन जल्द ही यह कल्पना साकार रूप लेने जा रही है। ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर में स्थित एयर-वन आपकी इस सोच को बदल देगी। दरअसल, फ्लाइंग कार लंबे समय से मानवों के लिए एक सपना रही है। जैसे-जैसे दुनिया ऐसे वाहनों के सपने को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रही है, ब्रिटेन में इस चमत्कार के लिए पहला एयरपोर्ट पहले ही खुल चुका है। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए एयर-वन का निर्माण किया गया है।

इस खास एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कोर्स, ड्रोन के लिए किया जाएगा। यही नहीं, इस एयरपोर्ट पर सभी चीजों की वर्टिकली लैंडिंग होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एयर टैक्सी हो या ड्रोन, सभी ऊपर से नीचे की तरफ सीधे उतरेंगे। इस वजह से रन- वे की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्पेशल एयरपोर्ट का इस्तेमाल लोगों के आवागमन और सामान की डिलीवरी को बेहतर और फास्ट बनाने के लिए किया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन स्थित अर्बन-एयर पोर्ट लिमिटेड (यूएपी) ने फ्लाइंग कारों के लिए एयरपोर्ट को फिनिशिंग टच दिया है। माना जाता है कि एयर वन नामक यह विशेष एयरपोर्ट केवल 15 महीनों में तैयार हुआ है। लंदन से करीब 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस सुविधा को अर्बन-एयर पोर्ट लिमिटेड और कोवेंट्री सिटी काउंसिल की साझेदारी से विकसित किया गया है। हालांकि, आपको बता दें कि एयर वन के फिलहाल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुलने की उम्मीद नहीं है। इसका कारण यह है कि फ्लाइंग कारें अभी तक बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। एयर वन एक पूरी तरह से ऑटोनमस सुविधा है, जिसमें शून्य कार्बन सार्वजनिक और शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इलेक्ट्रिक ड्रोन और एयर टैक्सी यहां आसमान में ले जाएंगे, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन जमीन पर चक्कर लगाएंगे। अर्बन-एयर पोर्ट लिमिटेड ब्रिटेन में ऐसे और एयरपोर्ट बनाना चाहती है। भविष्य में फ्लाइंग टैक्स

गुजरात ने पकड़ी बांस संवर्धन और बांस उद्योग का इकोसिस्टम खड़ा करने की दिशा: मुख्यमंत्री

- आदिवासी पट्टे के वनबंधुओं को 20 करोड़ रु. के 42 लाख बांस के निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का डेडियापाडा से शुभारंभ

भरुच (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 14 जिलों के आदिवासी बंधुओं को बांस आधारित रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की नई पहल के रूप में अंबाजी से उमरगाम तक के आदिवासी पट्टे के वनबंधुओं को 20 करोड़ रुपए मूल्य के 42 लाख बांस का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम गुरुवार को डेडियापाडा से शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने 'हरा सोना' यानी बांस के संवर्धन और बांस उद्योग का इकोसिस्टम खड़ा करने की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांस को पेड़ मानने वाले 90 साल पुराने कानून को निरस्त कर आदिवासियों के व्यापक विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। इसके चलते देश के अनेक राज्यों में बांस आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी युवाओं के कौशल को व्यवस्थित ढंग से और समयानुकूल निखार देने के लिए 'प्रधानमंत्री कौशल्य वर्धन योजना' के अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बांस आधारित 4 कौशल वर्धन केंद्रों का लोकार्पण भी किया।

भूपेंद्र पटेल ने कुल 2 करोड़ रुपए के खर्च से डेडियापाडा, नेत्रंग, वघई और केवड़ी में तैयार बांस आधारित कौशल वर्धन केंद्रों का लोकार्पण करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित ये केंद्र 'वोकल फॉर लोकल' का लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में वनबंधुओं-आदिवासियों के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए सरकार की प्रतिबद्धता आज के इस समारोह के जरिए साकार हुई है।? उन्होंने कहा कि बांस के उत्पादों को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में यह कौशल वर्धन केंद्र 'ग्रोथ सेंटर' साबित होगा। प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शी आयोजन से सभी के लिए विकास के अनेक अवसर उपलब्ध कराकर गुजरात को विकास का रोल मॉडल और ग्रोथ इंजन बनाया है। बांस जैसी वन संपदा के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के जरिए आदिवासी समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वनबंधु कल्याण योजना के माध्यम से अतीत में आदिवासी समाज द्वारा सहन की गई कठिनाइयों को करोड़ों रुपए के भारी लाभ प्रदान कर दूर किया है। उन्होंने कहा कि आज जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित विज्ञान संकाय के अनेक कॉलेजों के कारण आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के स्वप्न साकार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों-आदिवासियों के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो अद्यतन सुविधा मुहैया कराई है, उसके परिणामस्वरूप ड्रॉप आउट अनुपात नीचे गिरा है और युवाओं को उच्च अध्ययन की सुविधा मिली है। पटेल ने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी और हाशिये पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने को सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में गरीब वर्ग को मुफ्त अनाज वितरण प्रदान कर, स्वदेशी वैक्सीन और बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए कोविड प्रबंधन का प्रेरक उदाहरण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की 25 सहभागी वन व्यवस्था समितियों को कुल 5 करोड़ रुपए के लाभ, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए के लाभ तथा 4 वनलक्ष्मी, इको डेवलपमेंट-इको टूरिज्म के लाभ वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने सखी मंडलों की माता-बहनों द्वारा बनाए गए पारंपरिक आदिवासी भोजन का भी लुत्फ उठाया। बांस कार्यशाला में उन्होंने बांस से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की गतिविधियों को भी बारीकी से देखा और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने वनबंधुओं को बांस का निःशुल्क वितरण किया तथा 'नमो वड वन-डेडियापाडा' का लोकार्पण करने के बाद वड यानी बरगद का पौधा रोपा और उसे पानी दिया। मुख्यमंत्री ने प्लेटिनम वन-गलतेश्वर और नांदोद तहसील के पवित्र उपवन-रामपरा का भी ई-लोकार्पण किया। प्रगतिशील वनबंधु किसानों और वन विकास का उम्दा कार्य करने वाली मंडलियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किया तथा गुजरात में बांस से संबंधित विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण 'बाम्बू रिसोर्स ऑफ गुजरात' नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री किरीटसिंह राणा ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के सूत्र को आत्मसात कर अनेक जनोन्मुखी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि वनबंधु योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं आदिवासी समाज के लिए लाभदायी बन रही हैं, इसी तरह, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 500 से अधिक मोबाइल टावर केवल 2 वर्षों में लगाए जाएंगे। राणा ने विश्वास व्यक्त किया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 4 कौशल वर्धन केंद्रों के माध्यम से आगामी समय में वनबंधु और भी ज्यादा रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनेंगे।

आदिजाति विकास मंत्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अंबाजी से लेकर उमरगाम तक के क्षेत्र में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू कर आदिवासी समाज को रोजगार मुहैया कराकर आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास किया है। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सरकार द्वारा आवंटित भारी धनराशि का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार वनबंधुओं के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

भरुच के सांसद मनसुख वसावा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली और सिंचाई जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। आदिवासी बंधु कौशल वर्धन केंद्रों के मार्फत स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है।

वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. राकेश ने कहा कि आदिवासी प्रजा ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखा है। वन विभाग द्वारा स्थानीय आदिवासी कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला यह संकुल आजीविका का प्रेरणादायी स्त्रोत बनेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का आदिवासियों की कुलदेवी देवमोगरा माता की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री का नर्मदा ज़िला प्रशासन को गंगापुर बांध बनाने के लिए तत्काल सर्वे पूरा कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का आदेश

नर्मदा (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा ज़िला प्रशासन को गंगागुप बांध निर्माण के लिए तत्काल सर्वे कराकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए सूचना दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा ज़िले के दूरदराज आदिवासी क्षेत्र डेडियापाडा में गुरुवार को बाँस आधारित कौशल वर्द्धन केन्द्र के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद ज़िले के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इस बैठक में सांसद, विधायकगण सहित उपस्थित अन्य पदाधिकारियों ने गंगापुर बांध को ध्यान में रखते हुए कहा कि गंगापुर बांध यहाँ के इलाकों के लिए आशीर्वादरूप बन सकता है तथा किसी भी प्रकार के निजी ज़मीन अधिग्रहण के बिना बांध का निर्माण हो सकता है। इसलिए यह बांध जल्द से जल्द मंज़ूर करने की स्थानीय लोगों की माँग है। इस बैठक में सांसद, विधायकगण साहित अन्य पदाधिकारियों ने राजपीपला शहर के पुराने सिविल अस्पताल को नवनिर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थानांतर करने, आदिवासी क्षेत्र के टयूबवेल आधारित खेती में बोर मोटर तथा इलेक्ट्रिक मोटर की सुविधा मुहैया कराने, करजण बांध के पास भारी बारिश से क्षरण के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल बनाने सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बैठक में कहा कि लोकशाही शासन प्रणाली में निर्वाचित लोकप्रतिनिधियों तथा ज़िला प्रशासन के बीच समन्वय से ही जनहित के मुद्दों का शीघ्र समाधान होता है। उन्होंने ज़िले में योजनाओं के क्रियान्वयन में सैचुरेशन प्वाइंट की भी जानकारी ली। इस बैठक में मंत्रीगण किरीटसिंह राणा, नरेश पटेल तथा राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, सांसद मनसुख वसावा, विधायक महेश वसावा, राजपीपला नगर पालिका के अध्यक्ष कुलदीपसिंह गोहिल, ज़िला भाजपा अध्यक्ष, नर्मदा शुगर फैक्ट्री तथा भरूच दूध धारा डेयरी के चेयरमैन धनश्याम पटेल, ज़िला कलेक्टर अंकित पन्नू, पूर्व मंत्री मोतीसिंह वसावा, शब्दशरण तडवी, हर्षद वसावा, नील राव सहित के अग्रणी, उच्च अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दो कारों के बीच जबर्दस्त भिड़ंत में नगर पालिका के दो कर्मचारियों की मौत, 2 जख्मी

देवभूमि द्वारका (ईएमएस) गुरुवार के तड़के देवभूमि द्वारका जिले में दो कारों के बीच हुई जबर्दस्त टक्कर में जामरावल नगर पालिका के दो कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए नगर पालिका के चारों कर्मचारी कचहरी के काम से तड़के कार में गांधीनगर के लिए रवाना हुए थे जानकारी के मुताबिक देवभूमि द्वारका जिले की जामरावल नगर पालिका के टेक्स विभाग में कार्यरत नितिन कागडिया, सेनेटरी इंस्पैक्टर मनोज सिंगरखिया, कनु कागडिया और केशू बारैया सरकारी कार्यवश गुरुवार तड़के बलेनो कार में गांधीनगर के लिए रवाना हुए थे रास्ते में बलेनो और अर्टिगो कार के बीच जबर्दस्त भिडंत हो गई जिसमें दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए इस हादसे में नितिन कागडिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि कनु कागडिया, केशू बारैया और मनोज सिंगरखिया को जामनगर के अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान मनोज सिंगरखिया ने भी दम तोड़ दिया

गुजशत में अन्य शज्यों के ७८५५६ पश्विाश 'वन नेशन वन शशन कार्ड' योजना से लाभान्वित हुए

गुजशत के ११ लाख ५८ हज़ाश २७७ पश्विाशों को अन्य ज़िलों से मिला शशन

गांधीनगर, २६ मई ।

गुजशत शज्य में जून २०२० से अप्रैल २०२२ तक अन्य शज्यों के ७८,५५६ पश्विाशों के लिए सार्वजनिक वितशण व्यवस्था के अंतर्गत शशन कार्ड मानो एटीएम कार्ड बन गया है।

वन नेशन वन शशन कार्ड योजना लागू होने के बाद शशन कार्ड के प्रत्येक शज्य में उपयोग के योग्य बन जाने के पश्णिामस्वरूप कार्ड धशकों को उनकी निकटस्थ किसी भी सस्ते अनाज की दुकान से सार्वजनिक वितशण व्यवस्था के अंतर्गत शशन मिलने लगा, जिससे लोगों को काफी सशलता का अनुभव हो शहा है । गुजशत में इस योजना के अंतर्गत लगभग ११ लाख ५२ हज़ाश ७७७ पश्विाशों को उनके ज़िलों के अलावा अन्य ज़िलों से शशन मिल शहा है । इस योजना से विशेष रूप से आदिवासी बहुल ज़िलों के प्रवासी श्रमिकों को फायदा हुआ है ।

क्या है वन नेशन वन शशन कार्ड योजना ?

इस योजना के सशलीकशण के अंतर्गत ह्.स्न.रू. अंतर्गत लाभार्थियों को देय शश देश, शज्य या ज़िले की किसी भी दुकान से समय पश, सशलता से व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कशने के लिए 'वन नेशन वन शशन कार्ड' योजना का क्रियान्वयन किया गया है ।

भाशत सशकाश द्वाश इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष २०१९ में किया गया है, जिसमें गुजशत शज्य का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन कश गुजशत तथा महाशष्ट्रशज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी द्वाश वितशण व्यवस्था लागू की गई औश आज देश के अधिकांश शज्यों को शामिल कश लिया गया है ।

समग्र देश के ह्.स्न.रू. अंतर्गत लाभार्थियों को इसका लाभ मिल शहा है । साथ ही ७४ लाख से अधिक शशन कार्ड धाशकों की ३.४८ कशोड़ कशोड़ जनसंख्या में अंत्योदय पश्विाशों को प्रतिपश्विाश ३५ किलोग्राम तथा प्राथमिकता वाले पश्विाशों को प्रतिव्यक्ति ५ किलोग्राम अनाज का वितशण किया जाता है । इसमें २ रुपए प्रतिकिलो गेहूँ तथा ३ रुपए प्रतिकिलो चावल का शहत पश वितशण किया जाता है ।

कैसे किया जाता है आवेदन ?

इस योजना के लाभों की विस्तृत जानकाशी लोगों तक सशलता से पहुँचाने के लिए भाशत सशकाश द्वाश 'मेश शशन' मोबाइल एप्लिकेशन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तैयाश की गई है । इस मोबाइल एप्लिकेशन द्वाश लाभार्थी अपना शजिस्ट्रेशन कशवा सकते हैं, अपनी निकटतम् सस्ते अनाज की दुकान की जानकाशी, उन्हें देय शशन सामग्री आदि का विवशण उंगलियों पश प्राप्त कश सकते हैं ।

ऑनलाइन गेम खेलने के लिए कातिल बना किशोर

खेड़ा (ईएमएस)। गुजरात के खेड़ा में एक ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक भाई ने दूसरे की जान ले ली। दरअसल, मोबाइल फोन को लेकर दो सगे भाईयों में लड़ाई हो गई। जानकारी के अनुसार, 16 साल के एक भाई ने अपने छोटे भाई की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कुंए में फेंक दिया। खेड़ा शहर पुलिस के उप निरीक्षक एस पी प्रजापति ने बताया कि घटना सोमवार को गोबलेज गांव में हुई और नाबालिग आरोपी को बुधवार को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, परिवार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का रहने वाला है और मजदूर का काम करने के लिए खेड़ा गांव में आया था। प्रजापति ने कहा कि 23 मई को दोनों भाई बारी-बारी से मोबाइल फोन पर गेम खेल रहे थे। इस बीच आरोपी ने अपने 11 वर्षीय छोटे भाई के साथ लड़ाई की। जिसने खेलने की बारी आने पर उसे मोबाइल देने से इनकार कर दिया था। गुस्से में किशोर ने अपने छोटे भाई के सिर पर एक बड़े पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में आरोपी का छोटा भाई बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी भाई ने तार लगे पत्थर से छोटे भाई को बांध दिया और पास के एक कुएं में फेंक दिया। इस वक्त घटनास्थल पर दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद, अपने माता-पिता को बताए बिना आरोपी नाबालिग एक बस में चढ़ गया और अपने गृहनगर राजस्थान चला आया। जब देर शाम तक माता-पिता अपने दोनों बेटों को घर पर नहीं मिले, तो उन्होंने अपने गृहनगर में पूछताछ की और अपने बड़े बेटे के बारे में जाना। जब वे उसे वापस लाए और उससे उसके छोटे भाई के बारे में पूछा, तो आरोपी ने उन्हें बताया कि एक लड़ाई के बाद उसने उसे मार डाला है। बुधवार को परिवार से घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के शव को कुएं से बाहर निकाला और नाबालिग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

हरामीनाला के निकट से चार बोट समेत पाकिस्तान के 2 मछुआरे पकड़े गए

कच्छ (ईएमएस) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने कच्छ के हरामीनाला के निकट से पाकिस्तान के दो मछुआरों को धर लिया साथ ही 4 बोट को भी जवानों ने कब्जे में ले लिया हैं घटना आज सुबह 8.30 की है जब बीएसएफ भुज की एक टीम हरामीनाला के निकट गश्त पर थी उस वक्त क्षैतिज चेनल के निकट पाकिस्तानी बोट की हलचल देख बीएसएफ की टीम वहां पहुंच गई बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के दोनों मछुआरों के साथ ही चार बोट भी जब्त कर ली बोट की जांच में मछलियां, मछली पकड़ने की जाली और अन्य साधनों के अलावा कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई हैं चार बोट बरामद हुई है, जबकि मछुआरे केवल दो पकड़े गए हैं फिलहाल बीएसएफ के जवान पूरे क्षेत्र में जांच कर रहे हैं

अस्पताल को बदनाम करने के आरोप में यूएन मेहता होस्पिटल का आरएमओ गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस) साइबर क्राइम ने फेक आईडी पर सोशल एकाउंट बनाकर अस्पताल को बदनाम करने के आरोप में अहमदाबाद की यूएन मेहता होस्पिटल के आरएमओ डॉ. कौशिक बारोट को गिरफ्तार कर लिया हैं दरअसल पिछले काफी समय से यूएन मेहता होस्पिटल को बदनाम करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही थी इस संदर्भ में यूएन मेहता होस्पिटल के निदेशक आरवेक पटेल ने अहमदाबाद साइबर क्राइम में शिकायत की थी पुलिस की जांच में पता चला कि अस्पताल के आरएमओ डॉ. कौशिक बारोट फेक आईडी पर अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए होस्पिटल और लोगों को बदनाम कर रहे थे जांच में यह भी खुलासा हुआ कि डॉ. कौशिक बारोट दूसरे के नाम का सिमकार्ड का उपयोग करते थे और मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन डाल रखी जिससे किसी को भी फोन करने पर मोबाइल नंबर दिखाई ना दे इतना ही नहीं जिसे फोन किया जाता था उसे पुरुष के बजाए महिला का आवाज सुनाई देता था इस खुलासे के बाद साइबर क्राइम ने यूएन मेहता होस्पिटल के आरएमओ डॉ. राकेश बारोट को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की हैं

1 जून 2022 से वरेठा-गांधीनगर मेमू स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय में बदलाव

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 09498 वरेठा-गांधीनगर कैपिटल मेमू स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09498 वरेठा-गांधीनगर स्पेशल 1 जून 2022 से वरेठा से 06:30 बजे चलकर 06:41 बजे खेरालु, 06:54 बजे वडनगर, 07:03 बजे गुँजा, 07:10 बजे विसनगर, 07:19 बजे पुड़गाम गणेशपुरा, 07:25 बजे रंडाला, 07:38 बजे महेसाणा, 07:50 बजे जगुदन, 08:00 बजे आंबलियासन, 08:11 बजे डांगरवा, 08:19 बजे झुलासण, 08:40 बजे कलोल तथा 09:30 बजे गांधीनगर पहुंचेगी। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गांधीनगर में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय आम महोत्सव 2022' का आयोजन, मुख्यमंत्री आज करेंगे उद्घाटन

अहमदाबाद (ईएमएस) 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत गुजरात सरकार के गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) द्वारा राजधानी गांधीनगर में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय आम महोत्सव 2022' का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में सेक्टर-11 स्थित रामकथा मैदान में आयोजित इस महोत्सव का 27 मई शुक्रवार को सुबह 8 बजे उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में पर्यटन तथा यात्राधाम विकास मंत्री पूर्णेश मोदी एवं पर्यटन तथा यात्राधाम विकास राज्य मंत्री अरविंद रैयाणी भी उपस्थित रहेंगे। यह महोत्सव तीन दिन यानि 29 मई तक चलेगा। टीसीजीएल की विज्ञप्ति के अनुसार इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में गुजरात सहित देश भर के विभिन्न प्रदेशों में उत्पादित अलग-अलग प्रकार के आमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें गुजरात के केसर, हाफुस, राजापुरी, जामदर, तोतापुरी, नीलम, दशेरी (दशहरी) व लंगडो (लंगड़ा) आम, पंजाब का चौसा व माल्दा आम, हरियाणा का फ़ज़ली आम, राजस्थान का बॉम्बे ग्रीन आम, महाराष्ट्र का पायरी, कर्नाटक का बंगनापल्ली व मालगोवा, आंध्र प्रदेश का सुवर्रेखा, मध्य प्रदेश का फ़ाज़ी, पश्चिम बंगाल का गुलाबखस व हिमसागर, बिहार का किसनभोग तथा जरदालू जैसे अनेक प्रकार के आम के प्रदर्शनी-सह-बिक्री स्टोल भी लगाए जाएँगे। तदुपरांत इस तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा बच्चों के लिए एक्टिविटीस का भी आयोजन किया गया है।

कम उम्र से ही कैसे काबू में रखें अपना वजन यास्मीन कराचीवाला

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने इसी महीने जारी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया कि 2030 कर हर 5 में से 1 महिला और हर 7 में से 1 पुरुष मोटापे से ग्रस्त होंगे। मिंट में दावा किया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 10.81 प्रतिशत बच्चों में मोटापा होगा और 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों तथा युवाओं में से 6.23 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त होंगे। इसलिए बहुत सोच-समझकर सही जीवनशैली चुननी चाहिए ताकि बाद के वर्षों में दिक्कत नहीं हो।

इस अध्ययन पर चिंता जताते हुए सेलेब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट यास्मीन कराचीवाला ने कहा कि माता-पिता और शैक्षिक संस्थानों के लिए बच्चों में फिट, सेहतमंद और सक्रिय जीवन जीने के लिए संतुलित जीवनशैली की आदतें डालना जरूरी है। साथ ही किशोरों की खानपान तथा जीवनशैली की आदतों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वे शारीरिक विकास के दिनों में बहक नहीं जाएं।

एल एंड टी बना दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन ब्रांड

ब्रांड फाइनेंस के 'सर्वाधिक मूल्यवान वैश्विक ई एंड सी ब्रांड्स' अध्ययन में जगह पाने वाला इकलौता भारतीय ब्रांड

मुंबई, 25 मई 2022:ईपीसी परियोजनाओं, उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण और सेवाओं में संलग्न भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) को दुनिया की अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी, ब्रांड फाइनेंस द्वारा शीर्ष 50 वैश्विक इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन (ई एंड सी) कंपनियों में 'दूसरे सबसे मजबूत ब्रांड' का दर्जा दिया गया है।

एल एंड टी को लंदन स्थित कंसल्टेंसी द्वारा अपनी 'इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन 50 - 2022' रिपोर्ट में 'थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड' के रूप में भी स्थान दिया गया है। यह 'सबसे मूल्यवान वैश्विक ई एंड सी फर्मों' में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। 50 देशों में अपनी मौजूदगी के साथ एल एंड टी ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने ब्रांड मूल्य में 44 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है।

इस उपलब्धि पर एल एंड टी के प्रवक्ता ने कहा, ठइस ब्रांड की पहचान सिर्फ इसके एक नाम या लोगो तक ही सीमित नहीं है। इसकी पहचान इसके द्वारा अर्जित विश्वास, प्रतिष्ठा, मूल्य प्रणाली और इसके साख से है। हम ब्रांड फाइनेंस द्वारा इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में दूसरे सबसे मजबूत वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह सम्मान हमारी टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और अपने वादों को पूरा करने की हमारी क्षमता में हमारे ग्राहकों के भरोसे का प्रमाण है।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95